Transfer of collectors in Kerala

2099. SHRI N. E. BALARAM:
SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government have asked for details of the transfers of all Collectors in Kerala before their completion of at least two years posting in the same place;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that the State Chief Minister has criticised this directive as a blatant and unnecessary interference in the administration of the State and violation of constitutional provisions; and

(d) if so, what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Yes, Sir. Recently, the Department of Personnel & Training as cadre controlling authority for IAS sent a request to all State Govts. including Kerala for sending certain information regarding postings and transfers of IAS officers as District Collectors.

(c) and (d) No communication in this regard has been received from the Chief Minister of Kerala. However, a report on the subject attributed to the Chief Minister, Kerala was carried in 'the Hindu' of 19th July, 1988. The Deptt. Personnel & Training in a letter to the Editor of the Hindu and published in that paper on 21st July, 1988 clarified the facts in order to set at rest all doubts on the subject.

2100. [*Transferred to the 17th August, 1988*]

Target of 10,000 MW of nuclear power

2101. SHRI KAPIL VERMA:
SHRIMATI VEENA VERMA:
KUMARI SUSHILA TIRIA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are Government's plans for achieving the target of 10,000 MW of nuclear power by the end of the country;

(b) what progress has been made so far in this regard;

(c) what will be the total cost of the project; and

(d) what are the plans to meet ecological and environmental dangers, because of the setting up of these nuclear power stations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) and (b) Currently six units are in operation with a total capacity of 1230 MWe. Eight units of 235 MWe each are under various stages of construction with two units each at Narora in Uttar Pradesh, Kakrapar in Gujarat, Kaiga in Karnataka and Rawatbhata in Rajasthan. On completion of these projects, the installed capacity would go upto 3110 MWe. Work on four more units of 235 MWe and six units of 500 MWe each is targetted for commencement during the 7th plan period. Six more units of 500 MWe each are also being planned for commencement during 8th plan period to raise the installed nuclear power capacity to about 10,000 MWe by the turn of the century.

(c) The total capital expenditure envisaged in the execution of the 10,000 MWe programme as per the Nuclear Power Profile is about Rs. 14,000 crores at 1983 prices.

(d) Protection of ecology and environment has always been given utmost importance during all stages of setting up of

Nuclear Power Plants, i.e. site selection, design, construction and operation of the Station. Clearance from environmental angle from the Ministry of Environment & Forests is obtained prior to setting up of the plants.

गुरुजल की पूर्ति और मांग

2102. श्री राम जेठमलानी :
श्री राम नरेश यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गुरुजल की पूर्ति और मांग में बहुत अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988–89 के दौरान गुरुजल की अनुमानित मांग और पूर्ति कितनी होगी ; और

(ग) इस संबंध में देश की मांग को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के आर नारायणन): (क) भारी पानी संयंत्रों मे उत्पादित भारी पानी देश की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त है। केवल राजस्थान परमाणु बिजलीघर के लिये आवश्यक भारी पानी आवश्यकता पड़ने पर सोवियत संघ से मंगाया जाता है।

(ख) चूंकि भारी पानी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पदार्थ है, अतः इसकी अनुमानित मांग और सप्लाई की जाने वाली मात्रा के बारे में बताना राष्ट्र हित में नही है।

(ग) इस समय चालू भारी पानी संयंत्रों के अतिरिक्त, दो और भारी पानी परियोजनायें निर्माणाधीन हैं एक मानुगुरु (आंध्र प्रदेश) में और दूसरी हजीरा (गुजरात) में। भविष्य में होने वाली भारी पानी की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से और परियोजनायें स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है।

देश में गुरुजल संयंत्र

2103. श्री राम जेठमलानी :
श्री राम नरेश यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने गुरुजल संयंत्र कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ये संयंत्र अपनी स्थापित क्षमता के अनुरूप गुरुजल का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, और

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है और देश में उनमें से प्रत्येक संयंत्र में वास्तव में कितना वार्षिक उत्पादन हो रहा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर नारायणन) : (क) इस समय देश में 6 भारी पानी संयंत्र काम कर रहे हैं।

(ख) यदि निवेशों की दृष्टि से देखा जाय तो संयंत्रों का उत्पादन-स्तर संतोषजनक रहा है।

(ग) जो संयंत्र इस समय चालू हैं उनकी वार्षिक क्षमता कुल मिलाकर 365 मीटरिक टन है। 295 मीटरिक टन वार्षिक क्षमता वाली दो और परियोजनयें निर्माणाधीन हैं चूंकि भारी पानी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पदार्थ है, अतः इसके उत्पादन संबंधी आंकड़े बताना राष्ट्र हित में नहीं है।